

शीर्षक: अजमेर जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन पर लघु शोध ग्रन्थ

पर्यवेक्षक: डॉ. मुजम्मिल हसन

परिचय:

अल्पसंख्यक को सामान्यतः उस समूह से लिया जाता है जो धार्म भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं कम संख्या में हो अर्थात् अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुमत से धार्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में हैं।

1992 में इसमें समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विरोधा में दो नई योजनाएँ जोड़ दी गईं।

- शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम।
- मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के दौरान शुरू की गई थी।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, जाना जाता है। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षा में क्रान्तिकारी तरह से प्रवेश किया है।

हर शिक्षक को इंटरनेट, ईमेल, कम्प्यूटर के बारे में ही नहीं उसे उपयोग में लेना आना चाहिए इसी संबंध में शोधकर्ता ने राजस्थान के अजमेर जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की आईसीटी के बारे में क्या दृष्टिकोण है तथा वे इस बारे में कितना जानते हैं, जानने की आवश्यकता हुई।

उद्देश्य:

- शहरी एवं ग्रामीण अल्पसंख्यक शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना है।
- अल्पसंख्यक विद्यालयों के महिला एवं पुरुष शिक्षकों के आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- कार्य अनुभव के आधार पर महिला एवं पुरुष अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं:

एच01 शहरी एवं ग्रामीण अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

एच02 अल्पसंख्यक विद्यालयों में महिला एवं पुरुष शिक्षकों में आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

एच03 कार्य अनुभव के आधार पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रक्रिया:

सर्वेक्षण प्रक्रिया

जनसंख्या:

शोध में जनसंख्या शब्द का अर्थ भिन्न होता है। जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है।

न्यादर्श:

जब किसी भी जनसंख्या इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों में से किसी चर या विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिये उनकी एक इकाई को चुन लिया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने 'उद्देश्यानुसार न्यायदर्शन विधि' का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श का आकार: -

अध्यापक - 40

शहरी शिक्षक - 20

ग्रामीण शिक्षक-20

पुरुष -10

महिला-10

पुरुष -10

महिला-10

उपर्युक्त अध्ययन में अभिवृत्ति मापनी, लिफ्ट मापनी का उपयोग किया गया है।

अध्ययन में शोधाकर्ता ने मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, टी-परीक्षण का उपयोग किया है।

शोधा के शैक्षिक निहितार्थ -

- अल्पसंख्यक एवं सामान्य विद्यालय के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति उच्च सकारात्मक उत्पा एवं प्रभावी तरीके से जागरुकता।
- आईसीटी के प्रति अभिवृत्ति कम है या नकारात्मक प्राप्त होने पर उनके दृष्टिकोण को सुधारने के लिये योजनाएँ चलाई जा सकती हैं।
- विद्यालयों में शिक्षकों के आईसीटी की उपयोगिता, अनुप्रयोग तथा इससे संबंधित सुविधाओं के बारे में जागरुक किया जा सकेगा।

भावी शोधाकार्य हेतु सुझावः

- वर्तमान लघुशोधा अल्पसंख्यक विद्यालयों के केवल 40 शिक्षकों को लेकर किया गया है उसे बड़े क्षेत्र में अधिका न्यादर्श लेकर शोधा किया जा सकता है।
- माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की आईसीटी के प्रति जागरुकता का अध्ययन।
- आईसीटी के प्रति भावी शिक्षकों की अभिवृत्ति की जागरुकता का अध्ययन।
- शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में अध्यापकों का अध्ययन हेतु शोधा परियोजनाएँ निर्मित की जाती हैं।

शोधा का निष्कर्षः

उपर्युक्त शोधा में शहरी एवं ग्रामीण अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का आईसीटी के प्रति अभिवृत्ति तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों में पुरुष एवं महिला शिक्षकों की आईसीटी के प्रति क्या अभिवृत्ति है तथा साथ ही कार्य अनुभव के आधार पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को आईसीटी के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया तथा इससे निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण विद्यालयों की अपेक्षा शहरी विद्यालयों के शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया।

- पुरुष व महिला की अभिवृत्तियों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। आईसीटी के प्रति उनका रुझान समान ही पाया गया।
- कार्यानुभव के आधार पर भी सकारात्मक अभिवृत्ति को ही पाया गया।

शीर्षक:

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 के प्रति अल्पसंख्यक शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

पर्यवेक्षक: डॉ. मुजम्मिल हसन

प्रस्तावना:

शिक्षा की प्रारम्भिकता एवं अनिवार्यता के बारे में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रदान की जाये।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। कुछ कारणों से इस व्यवस्था को कानूनी रूप नहीं दिया जा सका।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया। जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को क्रियान्वित किया गया तथा प्रत्येक माता-पिता/संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय कर्तव्य घोषित किया गया तथा 11वें मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल किया गया।

दिसंबर 2002 में बने संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 भाग 3 द्विमूल अधिकार में एक नई धारा 21ए जोड़कर 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात करता है। संविधान की धारा 21ए कहती है - “कानून, संकल्प द्वारा, राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

उद्देश्य:

1. आर.टी.ई. का अध्ययन
2. राजकीय और अराजकीय अल्पसंख्यक अध्यापकों में आर.टी.आई एक्ट 2009 के प्रति दृष्टिकोण की तुलना करना।
3. महिला एवं पुरुष अल्पसंख्यक अध्यापकों में आर.टी.आई. एक्ट 2009 के प्रति दृष्टिकोण की तुलना करना।

परिकल्पना:

1. कुल न्यादर्श अल्पसंख्यक अध्यापकों का आर.टी.आई. एक्ट 2009 के प्रति कुल दृष्टिकोण पर प्राप्त मध्य मान औसत के सार्थक अधिका है।
2. राजकीय व अराजकीय विद्यालय अल्पसंख्यक अध्यापकों में आर.टी.ई. एक्ट व इसके आयामों पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. महिला व पुरुष अल्पसंख्यकों अध्यापकों में आर.टी.ई. एक्ट 2009 व इसके आयामों पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. शोधा प्रक्रिया: सर्वेक्षण विधि

5. **प्रस्तुत शोधा के प्रतिदर्श का चुनाव:** प्रतिदर्श के लिए भरतपुर जिले के अल्पसंख्यक जिले के शिक्षकों को शोधाकर्ता ने कुल जनसंख्या के रूप में लिया। इस जनसंख्या में से स्तरित यादृच्छिक विधि से विद्यालय, लिंग, क्षेत्र, पद, योग्यता, प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षकों का चयन किया, जो कि शोधाकर्ता का प्रतिदर्श है।

कुल शिक्षक - 80

सरकारी शिक्षक-40

निजी शिक्षक-40

पुरुष-20

महिला-20

पुरुष-20

महिला-20

ग्रामीण-10 शहरी-10

ग्रामीण-10 शहरी-10

ग्रामीण-10 शहरी-10

ग्रामीण-10 शहरी-10

6. **शोधा उपकरण:** प्रतिदर्श में कई प्रकार के उपकरण होते हैं।

प्रश्नावली

अनुसूची

चित्रकन सूची

निर्धारण मापनी

अवलोकन

साक्षात्कार

बु) तालिका आदि।

शोधाकर्ता ने अभिवृत्ति मापनी एवं लिंकर्ट विधि का उपयोग किया है।

7. शोधा में प्रयुक्त सांख्यिकी: मध्यमान, मानक विचलन, टी-परीक्षण, ए-परीक्षण।

8. शोधा के निष्कर्ष एवं सुझाव:

कुल अल्पसंख्यक अध्यापकों में आर.टी.ई. 2009 के अध्ययन में सार्थक अंतर है तथा कुल अल्पसंख्यकों अध्यापकों में "आर.टी.ई. का प्रारम्भिक प्रावधान" आयाम के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व उच्च है।

राजकीय व अराजकीय विद्यालय के अल्पसंख्यक शिक्षकों में आर.टी.ई. एक्ट 2009 के अध्ययन में सार्थक अंतर नहीं है। परन्तु राजकीय में आर.टी.ई. का प्रारम्भिक प्रावधान आयाम के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व उच्च है।

महिला व पुरुष अल्पसंख्यकों शिक्षकों में आर.टी.ई. एक्ट 2009 के अध्ययन में सार्थक अंतर है, लेकिन महिला अल्पसंख्यक शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष अल्पसंख्यक शिक्षकों में आर.टी.ई. का प्रारम्भिक प्रावधान आयाम के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व उच्च है।

9. सुझाव:

1. शिक्षा के अधिकार के प्रति अल्पसंख्यक अध्यापकों के दृष्टिकोण पर शोधाकार्य माध्यमिक स्तर पर किया जा सकता है।
2. शिक्षा के अधिकार के प्रति अभिभावकों तथा अध्यापकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. शिक्षा के अधिकार के प्रति छात्र-छात्रों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है।
4. शिक्षा शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों के शिक्षा के अधिकार के प्रति अभिवृत्ति जानने के लिए शोधा कार्य किया जा सकता है।
5. शिक्षा का अधिकार के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पादित किया जा सकता है।